किसानों को खेत से फसल बेचने के लिये ई-मंडी प्लेटफॉर्म बनेगा

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कृषि, पशुपालन, डेयरी पर बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की

जयपुर, 3 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए बनाई गई योजनाएं उन्हें 'विकसित राजस्थान-2047' की यात्रा में भागीदार भी बना रही हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में कृषि, कृषि विपणन, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी और गोपालन विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में शर्मा ने कहा कि कृषि को रोजगारोन्मुखी व्यवसाय बनाने की दिशा में राज्य सरकार दूरगामी निर्णय ले रही है।

लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ती दर पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 1,000 कस्टम हायरिंग सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खेत से ही फसल बेचने की सुविधा देने के लिए ई-मंडी प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर फसलों के भंडारण के लिए आधारभूत ढांचे के निर्माण के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कृषि, कृषि विपणन, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी और गोपालन विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा की।

ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट (ग्राम)-2026 के सफल आयोजन के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि

- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने ग्लोबल राजस्थान एग्री टैक मीट (ग्राम) -2026 के सफल आयोजन के लिये प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये।**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप, राज्य में 'श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी' की स्थापना की जा रही है, जो मिलेट्स को बढ़ावा देगी। इसके अलावा दूध संकलन के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने, और मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में नए प्रोजेक्ट्स के लिए अनुपयोगी सरकारी इमारतों का उपयोग किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्थान किसान आयोग के वर्ष 2025 के अंतरिम प्रतिवेदन का विमोचन भी किया।

बिहार चुनाव की रणनीति पर भाजपा की अहम् बैठक

नयी दिल्ली, 03 सितबंर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति एवं तैयारी को लेकर बुधवार को यहां व्यापक चर्चा की।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इस संबंध में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में शाह के अलावा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार में पार्टी के प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सांसद संजय

- **मीटिंग में बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के आवंटन पर चर्चा की गई**

जायसवाल, बिहार के सह प्रभारी दीपक प्रकाश तथा कुछ अन्य नेता मौजूद थे।

बैठक में हुए विचार-विमर्श के बारे में अधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस अहम बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के अन्य दलों के साथ सीटों के आवंटन तथा पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार किया गया। माना जा रहा है कि भाजपा अन्य मुद्दों के साथ-साथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में एक मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने को भी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी।

जीएसटी काउन्सिल की समस्त सिफारिशें स्वीकार कीं, सभी राज्यों ने

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रैस कॉन्फ्रैंस कर बताया कि सभी राज्यों ने जीएसटी की दरों को तर्क संगत बनाने पर मंजूरी दी है

नई दिल्ली, 03 सितंबर। जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही, अब जीएसटी में 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के सिर्फ दो ही स्लैब होंगे। खास बात है कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीएसटी की दरों को युक्तिसंगत बनाने पर सभी राज्यों ने सहमति दी है। रोजमर्रा की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी की दरों को कम किया गया है।

इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, वहीं इस बैठक में परिषद के तमाम सदस्य भी शामिल हुए। बता दें कि इस बैठक में 33 सदस्यीय समिति, आठ साल पुराने जीएसटी कर-ढांचे में बड़े बदलावों पर चर्चा की है।

इस बैठक के बाद वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अब देश में जीएसटी की दरें सरल होंगी। फिलहाल अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं पर कई तरह की टैक्स दरें लागू हैं, लेकिन अब इसे दो स्लैब में समेटा गया है। इस बदलाव का मकसद टैक्स प्रणाली को आसान और पारदर्शी बनाना है, जिससे कारोबारियों और आम जनता दोनों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने

- **निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी में अब 5 व 18 प्रतिशत के दो ही स्लैब होंगे।**
- **नई दरें नवरात्रि के पहले दिन, यानि 22 सितम्बर से लागू हो जाएंगी। इससे आम आदमी की जरुरत का सामान सस्ता हो जाएगा।**

बताया कि दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी।

लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। ये स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे।

इन बदलावों का मकसद आम आदमी की जरूरतों के सामान को सस्ता करना और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को हतोत्साहित करना है।

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद हुए ऐलानों पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र के सभी जीएसटी प्रस्तावों को परिषद द्वारा मंजूरी मिलने पर खुशी है।

एसी और टीवी जैसे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगे। डाई फ्रूट्स, अचार, कॉर्न फ्लेक्स, चीनी और शुगर क्यूबस जैसे कई सामानों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, सीमेंट पर 28 फीसदी के बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। 1200 सीसी के अंदर आने वाली कारें और 350 सीसी के अंदर आने वाली बाइक पर जीएसटी की दर 18 फीसदी होगी, जबकि मिड साइज कारों पर जीएसटी की दर 40 फीसदी होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हेयर ऑयल, साबुन, बार, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वियर पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि यूएचटी दूध और ब्रेड पर जीएसटी की दर जीरो होगी।

सरकार ने कहा कि पान, मसाला, सिगरेट समेत अन्य शिन प्रोडक्ट्स पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, लग्जरी प्रोडक्ट्स पर भी 40 फीसदी जीएसटी होगा तथा कैफीनयुक्त पेय पदार्थ और कार्बोनेटेड ड्रिंक भी 40 प्रतिशत के दायरे में आएंगे।

'विचलित मत हों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किरणें दाग सकती है-चाहे वह जहाज़ पर लगी हों या ज़मीनी ट्रकों पर।

- **अमेरिका के साथ-साथ चीन की यह सामरिक ताकत भारत के लिये भी नींद उड़ाने वाला मुद्दा है। भारत की ऐतिहासिक भूल थी, प्राइवेट सेक्टर को, सेना के लिये हथियार व अन्य सामरिक महत्व के सामान बनाने की प्रक्रिया से दूर रखना।**
- **अतः अभी भारत का हथियार बनाने का ''आधारभूत औद्योगिक ढांचा'' अविकसित या अर्द्ध विकसित सा ही है, तथा चीन इस दौड़ में भारत से मीलों आगे हो गया है, और यह भारत के लिये वाकई में गहन चिन्ता का विषय है।**

भारत के लिए यह हथियार और सैन्य प्रणालियाँ कोई अनजान बात नहीं होंगी। हमारा सैन्य शीर्ष नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व चीन की क्षमताओं से परिचित होगा। सवाल यह है कि हम क्या कर रहे हैं ताकि चीन की बराबरी कर सकें या कम से कम उसके क़रीब पहुँच सकें। भारतीय सैन्य योजनाकारों और राजनीतिक नेतृत्व को आगे बढ़ना होगा। और आपातकालीन आधार पर रक्षा-औद्योगिक ढांचा तैयार करना होगा ताकि देश की सुरक्षा के लिए सबसे आधुनिक और सक्षम हथियारों का निर्माण किया जा सके।

भारत के लिए इस चीनी प्रदर्शन से सबसे बड़ी सीख सिर्फ़ रक्षा क्षमता की चिंता नहीं है, बल्कि अपनी घरेलू विनिर्माण क्षमता के विकास की चिंता है। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र को शामिल न करना और विदेश से हथियार ख़रीदने का विकल्प चुनना अब साफ़ तौर पर एक भारी गलती साबित हो रहा है, जिसने भारत और चीन के बीच रक्षा उत्पादन क्षमता में वर्षों का फ़ासला बना दिया है। अब समय आ गया है कि तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ। इसके लिए मज़बूत घरेलू अर्थव्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्र की ज़रूरत है। नीतियाँ उसी लक्ष्य को पाने के लिए बनानी होंगी।

एस. आई. पेपर लीक में एक और प्रोबेशनर गिरफ्तार

एस. ओ. जी. ने प्रोबेशनर एस. आई. अशोक सिंह को पुलिस लाइन अजमेर से गिरफ्तार किया

जयपुर, 3 सितम्बर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने पर प्रोबेशनर एसआई को गिरफ्तार किया है। आरोपित प्रोबेशनर एसआई अजमेर पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहा था।

एसओजी की जांच में सामने आया कि प्रोबेशनर एसआई ने आठ लाख रुपए देकर एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लिया, जिस के कारण लिखित परीक्षा में उसके 310.39 अंक आए। फिलहाल आरोपित प्रोबेशनर एसआई से एसओजी की टीम पूछताछ करने में जुटी है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) एसओजी वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए,

- **एस. ओ. जी. की जांच के अनुसार प्रोबेशनर एस. आई. ने आठ लाख रुपये में पेपर लिया था और इस कारण उसके लिखित परीक्षा में 310.39 नम्बर आए थे।**

पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने वाले प्रोबेशनर एसआई अशोक सिंह (30) निवासी खींवसर जिला नागौर हाल प्रशिक्षु पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) पुलिस लाईन अजमेर को गिरफ्तार किया है।

एसओजी की जांच में पता चला कि अशोक सिंह ने पूर्व में गिरफ्तार विनोद कुमार जाट उर्फ विनोद रेवाड निवासी रेनवाल जिला जयपुर से पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा से पहले आठ लाख रुपये में सौदा कर उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 का 14 सितम्बर को आयोजित होने वाला दोनों पारियों का पेपर लिया था। उसने दोनों पारियों की लिखित परीक्षा, परीक्षा से पूर्व लीक सॉल्वड पेपर विनोद रेवाड के मार्फत वाट्सअप पर प्राप्त कर पढ़कर परीक्षा दी । जिसके कारण आरोपित अशोक सिंह ने लिखित परीक्षा में कुल 310.39 अंक प्राप्त कर लिखित परीक्षा पास की। आरोपित अशोक सिंह का उपनिरीक्षक के पद पर अंतिम रूप से मेरिट क्रमांक 396 पर चयन हुआ था। एसओजी अब तक की जांच के बाद 55 प्रशिक्षु उप निरीक्षक सहित, 124 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं।

चंद्रशेखर की बेटी कविता ने पार्टी से इस्तीफा दिया

हैदराबाद/नयी दिल्ली, 03 सितम्बर। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री तथा विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के कविता ने पार्टी से निलम्बित होने के एक दिन बाद बुधवार को पार्टी तथा परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

बीआरएस के सहयोगी संगठन तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष, के कविता ने विधान परिषद की सदस्यता से अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंप दिया। इससे एक दिन पहले उन्हें उनके पिता और बीआरएस प्रमुख, के चंद्रशेखर राव ने पार्टी से निलंबित कर दिया था। कविता ने अपने चचेरे भाई एवं पूर्व मंत्री टी हरीश राव तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसके बाद पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। पूर्व लोकसभा सदस्य, के कविता ने पार्टी तथा विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा सौंपने के बाद यहां पत्रकारों से कहा, मैंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

चयनित एसआई अभ्यर्थियों ने डबल बैंच में अपील की

जयपुर, 3 सितंबर। एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ की ओर से दिए आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में अपील पेश कर दी है। अपीलार्थी विक्रम पंवार व अन्य की ओर से दायर इस अपील याचिका पर खंडपीठ 8 सितंबर को सुनवाई करेगी।

अपील में अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने बताया कि एकलपीठ ने अपने आदेश में एक ओर राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आरपीएससी को भेजने को कहा है, वहीं दूसरी ओर भर्ती रद्द करने की बात भी कही है। यह आपस में विरोधाभासी है। इसके अलावा एकलपीठ ने अपना संपूर्ण निर्णय एसओजी, महाधिवक्ता और राज्य सरकार की पहली रिपोर्ट पर ही आधारित रखा है। राज्य सरकार ने बाद में दूसरी रिपोर्ट में अपना रुख स्पष्ट करते हुए फिलहाल भर्ती रद्द नहीं करने की बात कही है, लेकिन एकलपीठ ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया। अपील

- **एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई 8 सितम्बर को होगी।**

में कहा गया है कि एक विषय पर जब राज्य सरकार की पुरानी सिफारिश या रिपोर्ट पर नवीन सिफारिश या रिपोर्ट आ जाती है तो पुरानी एक तरह से प्रभावहीन हो जाती है। राज्य सरकार ने अपनी नवीन सिफारिश में माना है कि भर्ती में शामिल दोषियों की पहचान कर उनकी छंटनी संभव है। वहीं, भर्ती होने के बाद अपीलार्थियों का प्रशिक्षण हो गया और वे परिवीक्षा काल में चल रहे हैं। एसओजी ने उनके खिलाफ भी जांच की थी, लेकिन उनके खिलाफ पेपर लीक से जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं मिला। ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि एकलपीठ ने गत 14 अगस्त को सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद 28 अगस्त को आदेश देते हुए भर्ती को रद्द करने के लिए राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आरपीएससी में देने को कहा था। वहीं, एकलपीठ ने इस भर्ती के पदों को साल 2025 की भर्ती में जोड़ते हुए दूसरी सरकारी सेवा छोड़कर आए चयनितों को पूर्व की सेवा में लेने को कहा था। एकलपीठ ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में लगाने को कहा था। इस स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका पर खंडपीठ 10 सितंबर को सुनवाई करेगी।

उपराष्ट्रपति चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनाव एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली से होता है। इसमें सांसद उम्मीदवारों के नाम के आगे प्राथमिकता अंकित करते हैं। पहली प्राथमिकता अनिवार्य है, जबकि बाकी प्राथमिकताएं वैकल्पिक हैं। पहली प्राथमिकता यदि नहीं दी गयी है तो वोट अमान्य हो जाता है। मतदान के समय चुनाव आयोग विशेष पैन देगा और किसी अन्य पैन से डाला गया वोट मान्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन के बीच है।

'एक राज्य में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पूर्व केन्द्रीय मंत्री आनंद शर्मा, जिन्होंने वकील के रुप में वापसी की है, ने हिमाचल प्रदेश की ओर से कहा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधानसभाओं को बुलाते तक नहीं हैं। यह प्रक्रिया संसदीय कार्य मंत्री से शुरू होती है। कर्नाटक की ओर से एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी राज्य में दोहरी सत्ता (राज्यपाल और राज्य सरकार दोनों) नहीं हो सकती।

'बाढ़ग्रस्त राज्यों के लिए पैकेज दे केन्द्र सरकार'

नयी दिल्ली, 03 सितंबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में भारी बारिश से मची तबाही पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इन राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित करने की मांग की है। गांधी ने कहा कि इन राज्यों की स्थिति आपदाओं के कारण अत्यंत वीभत्स हो गई है और वहां जन जीवन संकट में आ गया है, इसलिए सरकार को प्रभावित राज्यों के लिए और विशेषकर किसानों के हित में विशेष राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सोशल मीडिया एक्स पर बुधवार को एक पोस्ट में प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा ''मोदी जी, पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है।

रूपवास थाने में हैड कॉन्स्टेबल ने आत्महत्या की

परिजनों के अनुसार वह लम्बे समय से बीमार था और अवसाद से जूझ रहा था

रूपवास/भरतपुर, 3 सितम्बर (निसं)। भरतपुर के रूपवास थाने में एक हेड कॉन्स्टेबल ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें फंदे पर लटके देखा तो सीनियर अफसरों को सूचना दी। मामला भरतपुर के रूपवास थाना इलाके का बुधवार शाम पांच बजे का है। परिजनों ने रिपोर्ट में बताया कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अवसाद से जूझ रहे थे।

पुलिस के अनुसार, रूपवास थाने में बदन सिंह जाट हेड कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात थे। उन्होंने बुधवार शाम करीब पांच बजे थाना परिसर में स्थित अपने कमरे (क्वार्टर) के बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही

- **हैड कॉन्स्टेबल बदन सिंह ने थाना परिसर में अपने आवास के बाथरूम में फांसी लगा कर आत्महत्या की, वह डेढ़ माह पहले ही प्रमोट होकर हैड कॉन्स्टेबल बना था।**

पुलिसकर्मियों ने उन्हें फंदे पर लटके देखा तो अधिकारियों को इसकी सूचना दी। अभी तक पुलिसकर्मी के सुसाइड के कारणों का पता नहीं चला है।

एडिशनल एसपी (बयाना) हरिराम कुमावत ने बताया कि रूपवास थाना परिसर में जो आवास बने हैं, उसके कमरे के बाथरूम में बदन सिंह लटके हुए मिले। इसके बारे में परिजनों ने रिपोर्ट पेश की है। बदन सिंह दौलतपुर थाना चिकसाना के रहने वाले थे। जिस कमरे में फंदा लगाया गया, उसे सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, बदन सिंह डेढ़ महीने पहले ही कॉन्स्टेबल से प्रमोट होकर हेड कॉन्स्टेबल बने थे।

घटना की सूचना पर एएसपी एडीएफ बयाना हरीराम कुमावत, सीओ नीरज भारद्वाज, रुदावल थानाधिकारी बालकृष्ण फौजदार, थानाधिकारी चंद्रमोहन, खेरिया मोड़ चौकी इंचार्ज घनश्याम पोषवाल, बंध बारैठा चौकी इंचार्ज भरतलाल व विनोद शर्मा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। एफएसएल और क्यूआरटी टीम की मौजूदगी में शव को फंदे से उतारकर एम्बुलेंस के जरिये उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। चिकित्सकों ने देर शाम होने के कारण पोस्टमार्टम गुरुवार सुबह करने की बात कही।

एन. डी. ए. का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की महिलाएं नहीं सहेंगी और इसीलिए बंद के साथ सड़कों उतरने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि अपने खिलाफ अपशब्द की वेदना से एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भावुक हो गये थे। उन्होंने कहा कि बिहार में राजद-कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गालियां दी गईं, जो न केवल उनकी मां का अपमान है, बल्कि देश की सभी मां, बहनों और बेटियों का भी अपमान है।

द्वितीय विश्व युद्ध में, जापान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

70 मिनट तक चला यह कार्यक्रम चीन की सैन्य शक्ति और कूटनीतिक प्रभाव को दर्शाने के लिए तैयार किया गया था।

माओत्से तुंग स्टाइल का ट्यूनिक सूट पहने राष्ट्रपति शी ने खुली छत वाली लिमोज़िन से सैन्य परेड और सैन्य उपकरणों का निरीक्षण किया।

परेड में अत्याधुनिक हथियारों की झलक देखने को मिली, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, पानी के भीतर चलने वाले ड्रोन और एक हथियारबंद रोबोट भेड़िया शामिल थे।

समारोह का समापन हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों की एक साथ उड़ान हुई और इसके बाद 80,000 पीस बड्र्स को उड़ाने के साथ हुआ।

पश्चिमी देशों द्वारा अलग-थलग किए गए पुतिन और किम की मौजूदगी इस परेड की एक खास विशेषता रही, जो क्रमशः यूक्रेन युद्ध और उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के चलते आलोचना में रहे हैं।

इस कार्यक्रम के बाद घनिष्ठ बीजिंग, मॉस्को और प्योंगयांग के बीच रक्षा संबंध की अटकलें तेज हो गई हैं, खासकर रूस और उत्तर कोरिया के बीच जून 2024 में हुए समझौते के बाद।

विशेषज्ञ यह भी देख रहे हैं कि क्या चीन और उत्तर कोरिया के बीच भी इसी तरह का गठबंधन बनता है - ऐसा होने पर यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सैन्य संतुलन बदल सकता है।

चीन के इस शक्ति-प्रदर्शनी पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सतर्क और कूटनीतिक रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इस कार्यक्रम की आलोचना करते हुए राष्ट्रपति शी पर "अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचने" का आरोप लगाया, जिसमें पुतिन और किम भी शामिल हैं।

ट्रंप ने सवाल उठाया कि क्या चीन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदानों को याद करेगा, जिन्होंने चीन की आजादी में मदद की थी।

उन्होंने लिखा, "सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति शी अमेरिका द्वारा चीन की स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदानों को स्वीकार करेंगे। बहुत से अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। मुझे आशा है कि उन्हें उनके साहस और बलिदान के लिए उचित सम्मान और स्मरण मिलेगा!"

उन्होंने आगे जोड़ा, "मैं राष्ट्रपति शी और चीन के महान लोगों को इस जश्न के लिए शुभकामनाएं देता हूं। कृपया मेरी ओर से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को भी गर्मजोशी से नमस्कार दें, जब आप अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचें!"

हालांकि, ट्रंप ने पहले पत्रकारों से कहा था कि वह इस परेड को अमेरिका के लिए सीधी चुनौती के रूप में नहीं देखते। जापान के शीर्ष सरकारी प्रवक्ता ने परेड पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं "रचनात्मक संबंध" बना रही हैं।

राष्ट्रपति शी ने द्वितीय विश्व युद्ध को "चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान" का एक मोड़ बताया है, जहां जापान के आक्रमण से मिली अपमानजनक हार के बाद चीन एक वैश्विक महाशक्ति बना।

इस सप्ताह की शुरुआत में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में, शी ने नई विश्व व्यवस्था की अपनी कल्पना पेश की और "हठधर्मी शक्ति राजनीति" का विरोध करते हुए एकजुटता की अपील की यह अमेरिका की आलोचना के रूप में देखा गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान वैश्विक अस्थिरता का मुख्य कारण चीन नहीं बल्कि ट्रंप की एकतरफा नीतियाँ हैं।

परेड के बाद आयोजित एक स्वागत समारोह में शी ने कहा कि मानवता को "जंगल के कानून" की ओर लौटने से बचना चाहिए।

ताइवान, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, ने अपने नागरिकों से परेड में भाग न लेने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि इससे बीजिंग के क्षेत्रीय दावों को बल मिल सकता है।

ताइवान की राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा कि उनका देश बंदूक की नोक पर शांति का जश्न नहीं मनाता।

विश्लेषकों का कहना है कि यह परेड देश में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने और आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने के उद्देश्य से की गई थी।

चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चला रहा है। एक दर्जन से अधिक जनरलों को हटा दिया गया है, जिनमें से कई शी के करीबी माने जाते थे।

दूसरे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थिति उस वक्त और बिगड़ गई, जब वन मंत्री संजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ आक्रामक अंदाज में बढ़ने लगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बीच में आकर उन्हें रोका। अगर समय रहते हस्तक्षेप नहीं होता, तो सदन में टकराव की स्थिति बन सकती थी। बढ़ते हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के बीच इस तीखे टकराव से सत्र का माहौल पूरी तरह गरमा गया है। झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर कांग्रेस की मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस पर इस हादसे के राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है।

ब्यावर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होने का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाया था। अब विभाग 40 प्रतिशत या उससे ऊपर बधिर है या नहीं, इसकी जांच करेगा।

कैंसर की दवाएं, पनीर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और आइसक्रीम आदि पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत पर आ सकते हैं या पूरी तरह से हट सकता है।

कृषि और उर्वरक: सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया जैसे इनपुट्स पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव है।

वस्त्र: सिंथेटिक यार्न, मैन-मेड स्टेपल फाइबर यार्न, कालीन और हस्तशिल्प पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत पर लाया जा सकता है।

टॉयलेटरीज़: टूथपाउडर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और टूथपेस्ट को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया जा सकता है। शैम्पू, तेल और साबुन को भी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत श्रेणी में लाने पर विचार हो रहा है।

छाता: इसकी दर घटाकर 5 प्रतिशत की जा सकती है।

होटल बुकिंग: 7,500 रुपये तक किराए वाले होटल कमरों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है।

सरकार की योजना है कि 28 प्रतिशत श्रेणी में आने वाले 90 प्रतिशत सामान को 18 प्रतिशत श्रेणी में लाया जाए और 12 प्रतिशत श्रेणी से काफी सामान 5 प्रतिशत श्रेणी में कर दिया जाए। इससे घरेलू खपत बढ़ने की उम्मीद है और अनुमानित 50,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी।

कुछ सामान या सेवाओं, जैसे जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, जिन पर फिलहाल 18 प्रतिशत टैक्स लगता है, को जीएसटी ढांचे से बाहर करने के प्रस्ताव भी हैं।

तथापि कुछ "लग्ज़री" वस्तुएं, जैसे तंबाकू और महंगी गाड़ियां, साथ ही शराब, अब भी "शिन गुड्स" (स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं) की श्रेणी में रहेंगी और इस बार उन पर स्वास्थ्य उपकर (हैल्थ सैस) या ग्रीन एनर्जी उपकर लगाया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इसका फायदा मध्यम वर्ग को मिलेगा, क्योंकि "दैनिक उपयोग की वस्तुएं" (अभी स्पष्ट नहीं है कि इनमें कौन-कौन सी चीजें शामिल होंगी) और "आकांक्षी वस्तुएं" (लालकर वाली वस्तुएं) सस्ती होनी चाहिए। कर में कटौती से निर्माताओं को कीमतें घटाने की प्रेरणा मिलेगी। हालांकि, कमी उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी दर घटाई जाएगी, क्योंकि निर्माता अक्सर पूरी कटौती का लाभ नहीं देते। इसके बावजूद, इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होनी चाहिए।

उदाहरण के लिए, 28 प्रतिशत की उच्चतम श्रेणी से 18 प्रतिशत की मध्यम श्रेणी में सामान लाने से सैद्धांतिक तौर पर भारतीय उपभोक्ताओं को बड़ी बचत होगी, जो कीमत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील माने जाते हैं। और बढ़ी हुई बिक्री निर्माताओं की चिंता, जैसे घटे हुए लाभ मार्जिन, को संतुलित कर सकती है।

परिणामस्वरूप, ऐसे निर्माता, जो आम तौर पर श्रम-प्रधान क्षेत्रों, जैसे ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, अधिक कामगारों को नौकरी देने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

जीएसटी स्लैब्स में बदलाव से मांग बढ़ेगी, और उम्मीद की जा रही है कि इसका असर उस 50 प्रतिशत टैरिफ पर भी कम होगा, जो डॉनल्ड ट्रंप ने पिछले महीने अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाया था।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इं